**भारत सरकार**

**संचार मंत्रालय**

**दूरसंचार विभाग**

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न सं. 4093**

**उत्तर देने की तारीख 12 अगस्त, 2026**

**राज्य-संचालित कार्यान्वयन मॉडल**

**4093. श्री चमाला किरण कुमार रेड्डीः**

**श्री इटेला राजेंदरः**

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या तेलंगाना ने भारतनेट चरण-।। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 'राज्य-संचालित कार्यान्वयन मॉडल' का चयन किया है तथा टी-फाइबर परियोजना के दायरे में 10,757 ग्राम पंचायतों (जीपी) और मंडलों को जोड़ना शामिल है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या टी-फाइबर परियोजना की संरचना अनूठी है तथा ग्राम पंचायतों और मंडलों में इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रगति पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य में एकीकृत और समेकित नेटवर्क स्थापित करने के लिए बीबीएनएन द्वारा 9 जिलों (पूर्ववर्ती खम्मम, निज़ामाबाद और रंगारेड्डी) में निष्पादित नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन) चरण-। को सौंपे जाने का ब्यौरा क्या है;

(घ) एनओएफएन चरण-। नेटवर्क को भारतनेट चरण-।।। संरचना में परिवर्तित करने हेतु प्रस्तुत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्वीकृति का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या ग्रामीण ब्रॉडबैंड के प्रसार को बढ़ाने के लिए टी-फाइबर हेतु भारतनेट उद्यमी प्रोत्साहन योजना का विस्तार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या बैंक ऑफ महाराष्ट्र से 9.4 प्रतिशत की दर से पहले से लिए गए ऋण के वित्तीय बोझ से बचने के लिए टी-फाइबर (तेलंगाना सरकार) को 1,779 करोड़ रुपये का दीर्घकालिक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है और यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**

**संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री**

**(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)**

(क) से (च) जी, हाँ। तेलंगाना ने राज्य में भारतनेट चरण-II परियोजना को टी-फाइबर के माध्यम से लागू करने के लिए 'राज्य संचालित कार्यान्वयन मॉडल' अपनाने का निर्णय लिया है। जिसमें 10,787 ग्राम पंचायतों (जीपी) को शामिल किया गया है, जिनमें से 8,887 जीपी को भारतनेट चरण-II परियोजना के तहत जोड़ा जा चुका है।

इसके अलावा, भारत सरकार ने भारतनेट के चरण-I और चरण-II के तहत सृजित मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और नई ग्राम पंचायतों के लिए वृद्धिशील नेटवर्क के सृजन और मांग के आधार पर बिना ग्राम पंचायत वाले गांवों को जोड़ने और ग्राम पंचायतों के प्रचालन और रखरखाव के लिए संशोधित भारतनेट परियोजना (एबीपी) को अनुमोदन दे दिया है। भारत सरकार ने एबीपी में 12,769 ग्राम पंचायतों का उन्नयन करने और उन्हें जोड़ने के लिए 3,189 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ राज्य में संशोधित भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तेलंगाना सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है और इसके लिए करार पहले ही तेलंगाना सरकार के साथ साझा किया जा चुका है।

एबीपी के तहत, भारत सरकार से सब्सिडी सहायता के साथ भारतनेट उद्यमी (बीएनयू) मॉडल के माध्यम से तेलंगाना सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (एफटीटीएच) कनेक्शन का प्रावधान किया गया है।

***